थोक मूल्य सूचकांक और श्रम मूल्य सूचकांक में वृद्धि

883. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1979 में थोक मूल्य सूचकांक और श्रम मूल्य सूचकांक क्या था और अब क्या है ;

(ख) मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने के कारण क्या हैं और उसे रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि राज्य व्यापार निगम तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठान गैर-सरकारी उद्योगपतियों की तरह लाभ कमाने में लगे हैं और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) मूल्यों को स्थिर रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जून, 1979 के पहले चार सप्ताहों में थोक कीमतों का औसत सूचक अंक (1970-71-100) 209.8 रहा जबकि इसकी तुलना में फरवरी, 1979 में यह सूचक अंक 184.6 था। मई, 1979 में अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1960-100) 339 पर था जबकि इसके मुकाबले फरवरी, 1979 में यह सूचक अंक 329 था।

(ख) इस वर्ष कीमतों में वृद्धि होने के मुख्य कारण ये रहे हैं, अर्थात् (i) कुछ वस्तुओं, जैसे कि अलौह धातुओं सीमेंट, लोहा तथा इस्पात के प्रशासित मूल्यों में वृद्धि की अनुमति देना, (ii) मौसमी दबावों का असर, जैसे कि दूध तथा दूध उत्पादों और फलों तथा सब्जियों के मामले में, (iii) आयात की बढ़ी लागत, जैसे कि पैट्रोलियम उत्पादों तथा खाद्य तेलों की बढ़ी लागत तथा (iv) तीन लगातार वर्षों में अर्थात् 1976-77 से 1978-79 तक मुद्रा उपलब्ध में बढ़ी तेज रफ्तारी से ज्यादा दर के हिसाब से वृद्धि होना।

(ग) राज्य व्यापार निगम जैसे व्यापारिक संगठनों को वाणिज्यिक उद्योगों के रूप में कार्य करना पड़ता है और इस तरह उनको लाभ की एक मुनासिब मात्रा ही अर्जित करनी पड़ती है। फिर भी इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने का ध्यान रखा गया है कि वे अत्यधिक लाभोपार्जन न करने लगें, जोकि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के स्वास्थ्य के लिये हानि कारक है।

(घ) सरकार मूल्य स्थिति पर सावधानी पूर्वक नजर रखती है और जब कभी आवश्यक होता है, कीमतों की अनुचित वृद्धि को रोकने के लिये उचित उपाय करती है। हाल ही में रिज़र्व बैंक ने चीनी, तिलहन, वनस्पति तेलों तथा दालों जैसी संवेदनशील मूल्य वाली वस्तुओं के आधार पर ऋण देने की व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। एक अनिवार्य भी जारी किया गया है, जिसके अनुसार अनिवार्य निक्षेप योजना की राशि की वापसी अदायगी, जो इस वर्ष 6 जुलाई को की जानी थी, एक वर्ष के लिये रोक दी गई है। यह कदम सकल मांग पर अंकुश लगाने के लिये उठाया गया है।

Expenditure Incurred by Government on Foreign Tours of Private Individuals

884. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 868 on the 21st July, 1978 regarding expenditure on foreign tours of Government and private individuals and state :

(a) the details of expenditure incurred by the Government on foreign tours of private individuals during 1st April 1977 to 31st March, 1979 ;

(b) what was the purpose of the expenditure incurred by the Government on these individuals; and

(c) the address of each individual on which Government made expenditure during the last two years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Aid from Aid India Consortium

885. SHRI KANWAR LAL GUPTA :
SHRI DHARAMAVIR VASISHT :
SHRI D. AMAT :

Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) is it a fact that Aid India Consortium has pledged 3 billion U.S. dollars aid to India in its meeting held in Paris in the first week of June this year ;

(b) what is the increase, percentage-wise approximately of the aid given by the Consortium this year, over the last four years ; and

(c) the names of the countries and the organisations, which participated in the meeting at Paris and the pledges of aid made by them respectively to India this year, as well as during the last four years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE